

न्यूज़ टुडे

विदेश मंत्री ने भारत-चीन संबंधों में सुधार के लिए आठ सिद्धांतों को रेखांकित किया

- विगत वर्ष पूर्वी लद्दाख में हुए घटनाक्रम के उपरांत से भारत चीन संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई थी। वरिष्ठ कमांडर स्तर की वार्ता के 9वें दौर के दौरान ही उत्तरी सिक्किम के नाथू-ला में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष की एक और स्थिति उत्पन्न हो गई थी। (मानचित्र देखें)।
 - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 से पूर्व की "घटनाओं" ने भी दोनों देशों के मध्य सहयोग और प्रतिस्पर्धा के "द्वंद्व" को प्रतिबिंबित किया था। उदाहरण के लिए, चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के संयुक्त राष्ट्र की सूची में सूचीकरण में अवरोध उत्पन्न किया था, साथ ही भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता का भी विरोध किया था।
- इस पृष्ठभूमि में, विदेश मंत्री ने उचित मार्गदर्शन हेतु आठ बिंदु प्रस्तावित किए हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।
 - सीमा प्रबंधन पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करना।
 - वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का पूर्ण सम्मान करना।
 - बहु-ध्रुवीय एशिया, बहु-ध्रुवीय विश्व के आवश्यक घटकों में से एक है।
 - एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करना।
 - समग्र संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए सीमांत क्षेत्रों में शांति और धैर्य स्थापित करना।
 - उदीयमान शक्तियों के रूप में, प्रत्येक की अपनी आकांक्षाएं भी हैं और उनके इस लक्ष्य की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है।
 - परस्पर असहमतियों और मतभेदों का प्रबंधन आवश्यक है।
 - दोनों सभ्य राज्यों को सदैव दूरदृष्टि रखनी चाहिए।
- उन्होंने संबंधों को निर्धारित करने वाले कारकों के लिए तीन 'पारस्परिकताओं' (mutuals), यथा- पारस्परिक सम्मान (mutual respect), पारस्परिक संवेदनशीलता (mutual sensitivity) और पारस्परिक हित (mutual interests) को प्रोत्साहन देने का सुझाव भी दिया।



प्रधान मंत्री ने विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) दावोस एजेंडा को संबोधित किया

- दावोस एजेंडा कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतीपूर्ण नए संदर्भ में आवश्यक सिद्धांतों, नीतियों और साझेदारी को आकार प्रदान करने के लिए वैश्विक नेताओं का संघटन है।
 - एजेंडा के 7 मुख्य विषय हैं: ग्रह को कैसे बचाया जाए, बेहतर अर्थव्यवस्थाएं, कल्याण के लिए तकनीक, समाज और कार्य का भविष्य, बेहतर व्यवसाय, स्वस्थ भविष्य तथा भू-राजनीति से परे (विश्व स्तर पर सहयोग)।
- दावोस एजेंडा, WEF की "ग्रेट रिसेट पहल" (Great Reset Initiative) की भी शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य संयुक्त और अनिवार्य रूप से निष्पक्ष, टिकाऊ एवं प्रत्यास्थ भविष्य के लिए वैश्विक आर्थिक व सामाजिक प्रणाली की नींव स्थापित करना है। इसके 3 घटक हैं:
 - बाजार को उचित परिणामोन्मुख बनाना।
 - यह सुनिश्चित करना कि निवेश से साझा लक्ष्यों, जैसे कि समानता और संधारणीयता को बढ़ावा मिले।
 - लोक कल्याण के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के नवाचारों का दोहन करना।
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में
 - एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी फाउंडेशन संगठन है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार प्रदान करने के लिए व्यापारिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके वैश्विक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
 - यह वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
 - प्रमुख प्रकाशन: वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report), वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report), वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness report) आदि।

सरकार उच्चतर बाह्य वित्तपोषण (higher external financing) का विकल्प अपना सकती है

- सरकार को राजकोषीय घाटे के अंतराल की पूर्ति हेतु बाह्य वित्तपोषण के मार्ग का सुझाव दिया गया है।
- बाह्य वित्तपोषण देश के बाहर स्थित स्रोतों से उधार लिए गए धन को संदर्भित करता है। बाह्य ऋण को उसी मुद्रा में वापस भुगतान करना पड़ता है, जिसमें यह उधार लिया जाता है।
 - यह विदेशी वाणिज्यिक बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) आदि से और विदेशी राष्ट्रों की सरकार से प्राप्त किया जा सकता है।
 - ये वित्त मुख्य रूप से दीर्घावधि के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं और इन पर ब्याज दर बहुत कम होती है।
 - भारत का वर्तमान बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मध्य अनुपात 5 प्रतिशत से कम के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे न्यून है।
 - मेघालय में पाए जाने वाले कोयले के हल्केपन के कारण इस प्रकार के खनन का यहाँ प्रचलन है।
- अवसंरचना क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और दीर्घावधि वित्तपोषण की सुविधा के कारण, उच्च बाह्य वित्तपोषण एक बेहतर विकल्प होगा।
 - वित्त वर्ष-2021 में आरंभिक आठ महीनों (अप्रैल-नवंबर) में बाह्य वित्तपोषण के माध्यम से एकत्रित की गई राशि लगभग 38,495.5 करोड़ रूपए हो गई, जो बजट अनुमान का 833 प्रतिशत है।
- बाह्य वित्तपोषण (EF) का महत्व:
- यह भुगतान संतुलन के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा जुटाने हेतु सहायक होता है।
 - निजी निवेश के बहिर्गमन के प्रभाव (crowding out effect) को कम करने में सहायक होता है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण में वृद्धि करके निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता को कम किया जाता है।

प्रथम बार डार्क मैटर के द्रव्यमान की परास की गणना कर वैज्ञानिकों ने यह तथ्य प्रकट किया कि डार्क मैटर "सुपर हैवी" या "सुपर लाइट" नहीं है

- वैज्ञानिकों ने द्रव्यमान की सीमा को घटा दिया है, जिसके भीतर कण जो डार्क मैटर बना सकते हैं, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर वहाँ अवस्थित हो सकते हैं।
 - क्वांटम गुरुत्व आइंस्टीन की क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता की अवधारणाओं का एक संयोजन है। यह समझाने का प्रयास करता है कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के लघुतम कणों पर कैसे कार्य करता है।
- अनुसंधान से ज्ञात होता है कि डार्क मैटर के कण न तो सुपर लाइट (अति हल्के) और न ही सुपर हैवी (अतिभारी) हो सकते हैं, जब तक कि उस पर कोई बल कार्यरत न हो, जो अभी तक अज्ञात है।
 - यह अनुसंधान इस रहस्यमय बल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।
- डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 95% हिस्सा हैं।
 - आकाशगंगाओं को संबद्ध रखने के लिए मुख्यतः 27% डार्क मैटर को उत्तरदायी माना जाता है।
 - यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का एक अन्य 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से निर्मित है, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए उत्तरदायी है।
- डार्क मैटर प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अन्य रूपों के लिए पूर्ण रूप से अदृश्य है, जिसका वर्तमान उपकरणों के माध्यम से पता लगाना असंभव है।
 - हालांकि, इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाशगंगाओं के समूहों की गति और सबसे व्यापक पैमाने पर संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना को समझाने के लिए आवश्यक है।



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नीतिगत दरों में परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने 5% मुद्रास्फीति लक्ष्य की योजना निर्मित की है

- सरकार 1 अप्रैल, 2021 से ± 2% की सहिष्णु सीमा के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य को 5% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।
 - RBI अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्र सरकार RBI के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी।
 - केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 45ZB के तहत गठित की गई मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रिपो दर) निर्धारित करती है।
- वर्ष 2016 में सरकार ने मौद्रिक नीति ढांचे के तहत वर्ष 2016 से 31 मार्च 2021 तक 6% की ऊपरी सहिष्णुता सीमा और 2% की निचली सीमा के साथ 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधिसूचित किया था।
- निम्न मुद्रास्फीति सार्वजनिक और निजी ऋण के उच्च स्तर की संधारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करेगी, क्योंकि ऋण सामान्यतया सांकेतिक मूल्यों (nominal values) में अनुबंधित होते हैं। अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति, ऋण के वास्तविक मूल्य को उच्च बनाए रखेगी।
 - इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति के लक्ष्य को ऊपर की ओर संशोधित करने से RBI को महामारी-से प्रभावित अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दरों में कटौती करने का अवसर मिल जाएगा।
- हालांकि, हाल ही में RBI के विश्लेषण के अनुसार भारत के लिए 4% मुद्रास्फीति को बनाए रखना उचित है।

अन्य सुर्खियाँ

<p>इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 (India Justice report 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह रिपोर्ट 'टाटा ट्रस्ट्स एंड पार्टनर्स' की एक पहल है। ○ देश में महिलाओं के संदर्भ में आंकड़े: <ul style="list-style-type: none"> ➤ देश के सभी पुलिस कर्मियों में महिलाओं की भागीदारी 10% है (जनवरी 2017 में 7%)। जिसमें 25% महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार रैंक में शीर्ष स्थान पर है। ➤ देश में कुल जेल कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी 13% है (दिसंबर 2016 में 10%); ➤ सभी उच्च न्यायालयों में 29.3% महिला न्यायाधीश हैं (वर्ष 2017-18 में 26.5%)। ○ कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है, जो SC, ST और OBC वर्ग से अधिकारी संवर्ग और सिपाही वर्ग (constabulary) दोनों पदों पर अपना कोटा भरने में सफल रहा है।
<p>भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई), 2020 (Corruption Perception Index (CPI), 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों को विशेषज्ञों एवं व्यावसायिक व्यक्तियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान करता है। ○ इसमें 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 (शून्य) अत्यधिक भ्रष्ट और 100 अत्यधिक स्वच्छ छवि वाले देश को इंगित करता है। इस सूचकांक में 40 के स्कोर के साथ भारत को 86वां स्थान प्रदान किया गया है (वर्ष 2019 में 80वां स्थान)। ○ इस वर्ष जारी सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ○ इसके अतिरिक्त सोमालिया और दक्षिण सूडान को 12 अंकों के साथ 179वां स्थान (सूचकांक में अंतिम स्थान) प्राप्त हुआ है।
<p>नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंफॉर्मेटिक्स ने अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई (National Informatics Centre Services Incorporated (NICS) celebrates 25 years of establishment)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ NICS राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre: NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। ○ इस अवसर के दौरान, निम्नलिखित उत्पादों को प्रारंभ किया गया: <ul style="list-style-type: none"> ➤ तेजस (TEJAS)— यह एक आभासी आसूचना उपकरण (वर्चुअल इंटेलेजेंस टूल) है। यह अधिकारियों के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण डेटा विश्लेषण प्रदान करता है। ➤ ई-नीलामी भारत (e-Auction India)— यह सरकारी विभागों की नीलामी संबंधी अग्र और पश्च इलेक्ट्रॉनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ➤ वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल (Work from AnyWhere Portal)— यह सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमुख एप्लीकेशंस तक पहुँच में वृद्धि करेगा। साथ ही, उन तक पहुँच को आसान भी बनाएगा।
<p>बासमती चावल के लिए पाकिस्तान ने भौगोलिक संकेतक (GI) प्राप्त किया (Pakistan receives geographical indicator (GI) for basmati rice)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ भारत के विरोध के बावजूद, पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है। यह चावल की विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय अनागार तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ○ पाकिस्तान ने बासमती चावल को अपने उत्पाद के रूप में पंजीकृत करवाने के भारत के कदम के विरुद्ध यूरोपीय संघ में आपत्ति दर्ज की है। ○ GI वस्तु एक नाम या एक संकेत होता है, जो उन उत्पादों को दिया जाता है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इस विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उनमें विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा पाई जाती है। ○ GI को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (intellectual property rights: IPRs) के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।
<p>भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India: WII)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने WII की सलाह की उपेक्षा करते हुए 3 राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। ○ यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ○ उद्देश्य: <ul style="list-style-type: none"> ➤ यह संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व अकादमिक कार्यक्रम के अतिरिक्त वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में परामर्श प्रदान करता है। ➤ वन्यजीव संसाधनों पर वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण करना। ➤ वन्यजीव अनुसंधान, प्रबंधन और प्रशिक्षण पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना तथा विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन समस्याओं पर परामर्श प्रदान करना। ○ इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है।
<p>लाला लाजपत राय (28 जनवरी 1865-1928) (Lala Lajpat Rai (28 January 1865-1928))</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ वे 'पंजाब केसरी' के नाम से भी लोकप्रिय थे। ○ उनका योगदान <ul style="list-style-type: none"> ➤ उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल (Dayanand Anglo-Vedic School) की स्थापना में सहायता प्रदान की थी। ➤ पंजाब नेशनल बैंक और हिंदू अनाथ राहत आंदोलन (Hindu Orphan Relief Movement) की नींव रखी थी। ➤ वर्ष 1917 में, न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। ➤ वर्ष 1920 में, कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ➤ वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन (Simon Commission) के विरुद्ध एक मौन मार्च का नेतृत्व किया तथा और एक लाठीचार्ज के दौरान लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी हत्या का प्रतिशोध भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने लिया। इन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ➤ उन्होंने ए हिन्दुस् इम्प्रेशन एंड ए स्टडी; हिस्ट्री ऑफ समाज; स्वराज और सामाजिक परिवर्तन, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया आदि की रचना की थी।
<p>पथरुघाट विद्रोह (Patharughat uprising)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह 1894 ई. में असम के दरंग जिले के एक छोटे से गाँव पथरुघाट में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उत्पन्न हुआ एक किसान विद्रोह था। ○ निहत्थे किसान भूमि राजस्व में वृद्धि का विरोध कर रहे थे और उन्होंने तय किया कि जब तक समस्या का उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक कोई लगान नहीं दिया जाएगा। ○ जब विरोध सभा चल रही थी, तब डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस को सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए और उनमें से लगभग 140 लोगों की मृत्यु हो गई थी।